

केंद्र परिचालित परियोजनाओं में सम्मिलित करने का है; और

(ग) क्या राजस्थान के सीमित संसाधनों के कारण इस योजना के पूरा होने में अनावश्यक विलम्ब हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) राजस्थान नहर पर कार्य मई, 1958 में प्रारम्भ किया गया था। मूलतः परियोजना का चरण—एक 1968-69 तक तथा चरण—दो 1977-78 तक पूर्ण होने प्रस्तावित थे। अब, वर्तमान संकेतों के अनुसार, परियोजना का चरण—एक 1973-74 तक और चरण—दो अगली योजनाओं में काफी हद तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(ख) राजस्थान नहर परियोजना जैसी बृहत् सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के प्रश्न की राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा जांच की गई थी और सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि ये परियोजनाएं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत ही रखी जाएं। फिर भी परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध संस्थाओं के अनुसार सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

राजस्थान में विद्युत् उत्पादन क्षमता

105. श्री शिवनाथ सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के अनुसार वर्ष 1970 की समाप्ति तक राजस्थान के लिए कितनी बिजली पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितनी बिजली पैदा की गई;

(ख) राजस्थान में कृषि के विकास को ध्यान में रखते हुए बिजली पैदा करने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) उन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1970-71 वर्ष के लिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य 12850 लाख किलोवाट आयोजन किया गया था। अद्यतन पूर्वानुमान के अनुसार, उत्पादन 11700 लाख किलोवाट होगा।

(ख) कार्यान्वयनार्थ हाथ में ली गई अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

स्कीम का नाम	क्षमता	राजस्थान का भाग
(1) जवाहर सागर जल-विद्युत् स्कीम 50% भाग	3 × 33 मैगावाट	49.5 मैगावाट
(2) राणा प्रताप सागर अणु विद्युत् केन्द्र	2 × 200 मैगावाट	4060 मैगावाट
(3) ब्यास यूनिट-i (देहार)	4 × 165 मैगावाट	100 मैगावाट
(4) ब्यास यूनिट-ii (पोंग बाँध)	4 × 60 मैगावाट	140 मैगावाट

(ग) जवाहर सागर-जल विद्युत् स्कीम के 1972 में पूर्ण होने की संभावना है। राणा प्रताप सागर ग्रुप विद्युत् केन्द्र की 200 मैगावाट की प्रथम यूनिट के 1972 में और उसके पश्चात् दूसरी यूनिट के 1974 में चालू होने की संभावना है। ब्यास यूनिट-i और ब्यास यूनिट-ii के अन्तर्गत शेष सभी यूनिटों के पाँचवी योजना में चालू होने की संभावना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य बिजली बोर्ड में निम्नलिखित स्कीमों के कार्यन्वयन के लिए प्रस्ताव किया है :—

1. पलाना ताप केन्द्र (2 × 25 मैगावाट)

2. सवाई माधोपुर ताप केन्द्र (3 × 62.5 मैगावाट)

इन स्कीमों की तकनीकी जांच हो रही है।

Regulation of voltage and Reduction in Frequency of Interruptions in Power Supplies

106. SHRI D. D. DESAI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the steps Government have taken or the regulation of voltage and reduction in frequent interruptions in the supply of power in the countries ;

(b) whether the cost of power generation and the rates charge from the public have gone down progressively all the world over; and

(c) if so, the steps Government have taken or propose to take for reducing the cost of power due to economy of scale?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWARPRASAD) :

(a) Great emphasis is being laid in developing and strengthening grid net-works all over the country.

Advantage of technological developments is being continuously taken, power research is being stepped up and sophisticated features are being introduced increasingly in the planning, designing and maintenance of power systems. These are :

- (i) Use of high speed switchgears and relays.
- (ii) Adequate protection against lightning for sub-stations and transmission lines.
- (iii) Use of shunt capacitors and synchronous condensers.
- (iv) Quick response excitation at the generating stations.
- (v) Live line maintenance of transmission lines.
- (vi) Systematic maintenance scheduling of transmission system and generating plant.
- (vii) Use of underground cables in congested urban areas.
- (viii) Limiting the lengths of rural feeders to a maximum of 30 to 40 KM and loading to 1 MVA.
- (ix) Arrangements for training operating personnel for Power Stations and live line maintenance of transmission lines.

A committee is already making a comprehensive study of the problems of power supply in rural areas in consultation with the State Electricity Boards.